मोदी सरकार का कांग्रेस के काले कारनामों पर "श्वेत पत्र" जारी

श्वेत पत्र में यू.पी.ए. के शासन काल, 2004-2010 में हुए 15 प्रमुख "स्कैम्स" की विस्तृत जानकारी दी गयी

■ **यह श्वेत पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यू.पी.ए. सरकार के शासन काल में देश की इकॉनमी पर चर्चा करते हुए संसद को दिया।**

नई दिल्ली, 08 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 2014 के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक श्वेतपत्र पेश किया। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में वर्तमान केंद्र सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में बताया गया है कि, तत्कालीन सरकार आर्थिक क्रियाकलावों को सुचारु रूप से चलाने में विफल रही थी। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय देश को और पीछे की ओर ले गए। सरकार ने कहा कि, यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां जब वे सत्ता में आए औसत दर्जे की थीं, जैसे-जैसे दशक बीतता गया वे और खराब होती गईं।

सरकार ने श्वेत पत्र में बताया कि, यूपीए काल के शासक न केवल अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को इस तरह लूटा कि हमारे उद्योगपतियों ने रिकॉर्ड पर कहा कि, वे भारत के बजाय विदेश में निवेश करना पसंद करेंगे। निवेशकों को भगाना आसान है लेकिन उन्हें वापस जीतना कठिन है। सरकार ने श्वेत पत्र में कहा कि, तत्कालीन यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी और उन्होंने 10 साल बाद हमें एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था दी। अब हमने इसकी जीवंतता बहाल कर दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान अंधाधुंध राजस्व व्यय, बजट के अतिरिक्त उधारी और बैंकों के एनपीए के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपीए के कार्यकाल में 15 घोटाले हुए।

कुल 59 पेज वाले 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' के मुताबिक, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और सार्वजनिक वित्त खराब स्थिति में था। साथ ही आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनुशासनहीनता और व्यापक भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था।

ऐसे में मोदी सरकार पर चुनौतियों से निपटने और अर्थव्यवस्था में गति एवं आशावाद को बहाल करने की जिम्मेदारी आ गई। यह एक संकटपूर्ण स्थिति थी।

चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद मोदी सरकार के सुधारों से लगभग एक दशक में भारत पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल हो गया।

श्वेत पत्र में इस पर खेद जताया गया है कि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद किसी भी तरह से उच्च आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए यूपीए सरकार ने व्यापक आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे बदनाम विरासतों में एक थी।

श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन, 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी, राष्ट्रमंडल खेल एवं सारदा चिट फंड सहित 15 घोटालों को सूचीबद्ध करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार के इन मामलों ने अर्थव्यवस्था में लोगों के विश्वास को हिला दिया था। रक्षा तैयारियों को भी नीतिगत पंगुता का खामियाजा उठाना पड़ा। कमजोर नेतृत्व, इरादे और कार्रवाई की कमी से रक्षा तैयारियां पिछड़ गईं।

2013 में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से 1991 के भुगतान संतुलन संकट के एक बार फिर पैदा होने की आशंका पैदा हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार केवल छह महीने के आयात के लिए ही पर्याप्त था।

श्वेत पत्र में कहा गया, "पिछले दस वर्षों के कामकाज को देखते हुए हम विनम्रता और संतुष्टि से यह कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार की छोड़ी गईं चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है। "

श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. बता दें कि श्वेत पत्र पर शुक्रवार (9 फरवरी) को लोकसभा में बहस होने की संभावना है। चार घंटे की बहस के बाद वित्त मंत्री के जवाब देने की उम्मीद है।

हेमन्त सोरेन ई.डी. की कस्टडी में त्याग पत्र देने आये थे-राज्यपाल

रांची, 08 फरवरी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी कस्टडी में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए राजभवन पहुंचे थे।

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 26.5 घंटे के अंदर झारखंड में नई सरकार का गठन करा दिया। राज्यपाल ने गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से सूचना आई कि कस्टडी में होने के कारण हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए राजभवन आना चाहते है और त्यागपत्र देना चाहते हैं। मुख्य सचिव की ओर से फोन कर बताया गया कि मुख्यमंत्री कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ राजभवन आना चाहते हैं, प्रारंभ में उन्होंने तीन लोगों के साथ हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया, बाद में पांच लोगों को आने की इजाजत दी गई।

फिजी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समन्वय विभाग अनिल राजभर, जिलाधिकारी नितीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भव्य स्वागत किया।उप प्रधानमंत्री फिजी गणराज्य को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास के महासचिव चम्पत राय ने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में सुगमता पूर्वक व अयोध्या पुलिस की सुरक्षा में रामलला के दर्शन कराये। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास ने उन्हें प्रसाद दिया। उसके बाद वे लखनऊ के लिये प्रस्थान कर गये।

मोदी सरकार के बहुचर्चित श्वेत पत्र जारी होने से पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के कारनामों पर "ब्लैक पेपर" जारी किया

■ **ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने कहा कि, मोदी सरकार के दस साल, बड़े भारी गंभीर मुद्दों, जैसे महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं, बेरोजगारी व गैर भाजपा सरकार के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के साथ हुए अन्याय का काल हैं।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 फरवरी। यू.पी.ए. पर मोदी सरकार का बहु-प्रचारित वाइट पेपर (श्वेत पत्र) आने से पहले ही कांग्रेस न आज एक "ब्लैक पेपर" जारी किया जिसमें मोदी सरकार की विफलताओं को प्रमुखता से बताया गया है। इस पेपर में आरोप लगाया गया है कि, पिछले 10 वर्ष अन्यायपूर्ण थे, जिनमें बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, केन्द्रीय संस्थानों का पतन और गैर भाजपायी राज्यों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों से देश त्रस्त रहा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 54 पृष्ठों की एक "चार्ज शीट" जारी करके केन्द्र की मोदी सरकार पर अभियोग लगाए।

खड़गे ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा कि, "हम सरकार के खिलाफ एक "ब्लैक पेपर" ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भी संसद में अपने विचार प्रकट करते हैं, वह अपनी विफलताओं को छिपाते हैं।" खड़गे के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और सैयद नसीर हुसैन भी मौजूद थे।

कांग्रेस ने इसमें आरोप लगाया है कि, "मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, कृषि सैक्टर को नष्ट किया है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्रोत्साहन दिया है और देश के अल्पसंख्यकों के साथ भारी अन्याय किया है।"

"आर्थिक अन्याय" के मुद्दे पर ब्लैक पेपर, बेरोजगारी के संकट, नौकरियों की कमी और श्रमिकों की अल्प भागीदारी की बात करता है।

ब्लैक पेपर में कहा गया है कि, "मोदी सरकार कीमत वृद्धि पर चुप है। पैट्रोल, डीज़ल और दैनिक काम आने वाली वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं।"

वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को एक बड़ी गलती बताते हुए पार्टी ने कहा कि "विनाशकारी नोटबंदी" को सात साल बाद बीत चुके हैं, लेकिन इसके प्रभाव अभी भी देश को परेशान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए खड़गे ने उल्लेख किया कि, "जब कीमत वृद्धि के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गाँधी की बात करते हैं, लेकिन अब उनकी सरकार है और उन्होंने जो भी कुछ किया है उसका जवाब तो उन्हें ही देना चाहिए।"

खड़गे ने मोदी की दु:खती रग पर प्रहार करते हुए कहा कि, "मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी ली थी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देना सुनिश्चित किया था, लेकिन, यह स्वीकार करने के बजाए कि, वह ऐसा नहीं कर सके, प्रधानमंत्री नई गारंटियाँ देने लग गए हैं।

खड़गे ने आरोप लगाया कि, पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया है।

ब्लैक पेपर में यह भी आरोप लगाया गया है कि, "भारत चुनावी अधिनायकवादी बन चुका है। पेपर में वी-डैम इन्स्टीट्यूट का भी हवाला दिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि, मोदी सरकार ने देश के संघवाद को कमजोर किया है।

ब्लैक पेपर का लिंक शेयर करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्मरण किया कि, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 4 जनवरी 2014 को करीब 75 मिनट की अपनी एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में दूरगामी प्रभाव रखने वाले दो बयान दिए थे, जो आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं।

डा. मनमोहन सिंह ने पहली बात तो यह कही थी कि, "इतिहास मेरे प्रति सहृदय रहेगा" और दूसरी यह कि यदि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश के लिए यह विनाशकारी होगा।" उनकी ये दोनों ही टिप्पणियां आज की तारीख में सही साबित हुई हैं।

विदाई समारोह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए ताकि, देश की प्रगति यात्रा को किसी की नज़र ना लगे। प्रधानमंत्री ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि, जो लोग अच्छी संगत में रहते हैं उनमें भी वैसे ही गुण विकसित होते हैं और जो लोग बुरे लोगों के बीच रहते हैं वे दोषपूर्ण बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, नदी का जल तब तक ही पीने योग्य रहता है जब तक वह बहती रहती है और जैसे ही वह समुद्र में जा मिलती है उसका जल खारा बन जाता है। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण इस विश्वास के साथ पूर्ण किया और कहा कि, सेवानिवृत हो रहे सदस्यों के अनुभव प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने सबको बधाई दी और उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।

कार्मिक विभाग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पद खाली चल रहा है, जिसके लिए कई दिनों से अलग- अलग नामों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं।

ऐसे में मुख्यमंत्री सलाहकार के नामों की चर्चाओं के बीच धनराज सोलंकी के नाम का एक आदेश जारी हो गया, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया। जैसे ही यह नाम सबके सामने आया मानो खलबली मच गई। आनन-फानन में आदेश को रोका गया और चार घंटे बाद संशोधित आदेश जारी करते हुए धनराज सोलंकी को सोशल मीडिया और आईटी सलाहकार बनाया गया। मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी होने के बाद से लगातार धनराज सोलंकी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था। धनराज सोलंकी पहले से ही भाजपा आईटी विभाग में काम देख रहे हैं।

नीरज चोपड़ा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपना एक भाला भी दिया और इसे पट्टिका के साथ ही रखा गया है। इस तरह वह रॉजर फैडरर और गॉल्फर रोरी मैकलरॉय जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गये जिनकी "आइस पैलेस" में ऐसी ही स्मारक पट्टिकायें हैं।

चोपड़ा ने पट्टिका के अनावरण पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, "इस देश में मुझे जो प्यार और सराहना मिली है, उससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैंने सपने में इस शानदार "आइस पैलेस" में पट्टिका लगाये जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, फिर भी मैं यहां हूं।"

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं, जैसे कि मैं यूरोप के शिखर पर खड़ा हूं।" चोपड़ा ने अपने भाला फेंकने के कौशल का प्रदर्शन करके "आइस पैलेस" में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

चोपड़ा ने इससे पहले स्विट्जरलैंड में ओलंपिक संग्रहालय को एक भाला उपहार में दिया था।

दिया कुमारी ने अपने पहले बजट में जयपुर का पूरा ध्यान रखा

■ **सीतापुरा से विद्याधर नगर मैट्रो सेवा का विस्तार होगा।**

■ **जयपुर में आई.टी. और फायनैंस कम्पनियों के लिये हाई टैक सिटी तथा ओलंपिक की तैयारी के लिये सेन्टर बनेगा।**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 8 फरवरी। भजनलाल सरकार के कार्यकाल के पहले बजट लेखानुदान में गुरूवार को विधानसभा में राज्य की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर में सीतापुरा से विद्याधर नगर तक मेट्रो चलाने, फाइनेंस कंपनियों के लिए हाईटेक सिटी बनाने और ओलिंपिक की तैयारी के लिए सेंटर खोलने जैसी कई घोषणाएं की।

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो के फेज-2 (सीतापुरा से अंबाबाड़ी) का विस्तार करके उसे विद्याधर नगर तक करने की घोषणा की है। गहलोत सरकार के समय फेज-2 की पहली डी.पी.आर. बनाई जा चुकी है। वर्ष 2012 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से बनवाई डी.पी.आर. में 23 किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित किया था। इस ट्रैक को बनाने में करीब 10 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी। सरकार ने बाद में इस रूट पर आने वाली लागत को कम करने के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करवाई। इसमें अंडरग्राउंड ट्रैक की लंबाई कम करके उसे एलीवेटेड किया गया और ट्रेन को जेएलएन मार्ग (एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक) के स्थान पर सीधे टोंक रोड से निकाला गया। संशोधित डीपीआर में लागत कम होकर 6500 करोड़ रुपए आई।

उपमुख्यमंत्री ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा की है। इससे पहले गहलोत सरकार ने पिछले बजट में भी इन्ही शहरों के लिए 500 बसें सर्विस मॉडल पर खरीद करने की घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी थी। इन 500 में से 300 बसें जयपुर के लिए आनी थी।

दिया कुमारी ने जयपुर शहर के नजदीक सरकार ने हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की है। इस सिटी में सरकार आईटी, फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी-अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित करेगी। इसके लिए बाकायदा इन कंपनियों को सरकार की तरफ से जमीन खरीद और दूसरे टैक्स में इन्सेंटिव दिया जाएगा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी ऐसी ही सिटी अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज के नाम से शुरू की थी। इसमें कुछ मल्टी नेशनल टेक कंपनियों, इंटरनेशनल बैंक ने अपने ऑफिस और यूनिट्स शुरू भी की है। हालांकि पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण अब यहां कंपनियां ज्यादा रुचि नहीं ले रही हैं। 15 साल पहले सरकार ने दिल्ली रोड पर अचरोल के पास करीब 1 हजार बीघा जमीन पर साइंस टेक सिटी बनाने की भी घोषणा की थी।

जयन्त भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि, भाजपा ने जयन्त को उनके परम्परागत मजबूत गढ़ में उनकी पसंद की सीटें देने का प्रस्ताव किया है। हाल ही के दिनों में जयन्त चौधरी को भाजपा के प्रति नरम रूख का प्रदर्शन करते देखा गया है। पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, 11 फरवरी को अयोध्याधाम मंदिर जाने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि, उनकी पार्टी के नेता अयोध्या दर्शन के लिए किसी अन्य तारीख को बाद में जाएंगे। चौधरी ने हाल ही के दिनों में पार्टी के दो कार्यक्रमों को आगे के लिए टाल दिया, जिसमें एक युवा सम्मेलन है जिसका आयोजन मथुरा में 4 फरवरी को होने वाला था। दूसरा कार्यक्रम उनके दादा, स्व. चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण 11 फरवरी 24 को किया जाना वाला था, उसे भी स्थगित कर दिया गया। स्पष्ट है, चौधरी अपने राजनीतिक भविष्य से संबंधित विकल्पों का आकलन कर रहे प्रतीत होते हैं।

जस्टिस खानविलकर अगले लोकपाल बनेंगे

नई दिल्ली, 08 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एम. खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी।

जस्टिस खानविलकर 29 जुलाई, 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी अगुवाई में ही पीठ ने पीएमएलए अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया था। पीठ ने ईडी के समन, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती के अधिकार को सही ठहराया था. साथ ही ईडी अधिकारियों के सामने इकबालिया बयान का उपयोग करने के लिए व्यापक अधिकार दिए थे।

जस्टिस खानविलकर ने उस पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने वाला फैसला सुनाया था। उसी मामले में प्रधानमंत्री को दंगा मामले में फंसाने के लिए मनगढ़ ंत सबूत पेश करने के लिए याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद तीस्ता को गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस खानविलकर ने उस पीठ का भी नेतृत्व किया था जिसने कई आपत्तियां उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था।

यू.पी.ए. प्रथम प्लस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगी। कमेटी ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकी।

इण्डिया गठबंधन के अहम नेता रहे नीतीश कुमार, राहुल गाँधी की टीम द्वारा उन्हें इच्छित पद ना दिए जाने के कारण गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ चले गए हैं।

आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने स्पष्ट कर दिया है कि, वह कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने की इच्छुक नहीं है। दोनों ही पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ेंगी।

अब तक वार्ताएं करते रहे केजरीवाल के साथ किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि, दिल्ली में किसी प्रकार का गठबंधन होने के संभावना नहीं है।

उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, हालांकि सूत्र कहते हैं कि, अखिलेश और समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह के गठबंधन की संभावना बिल्कुल नगण्य है।

अखिलेश यादव के नजदीकी सूत्र खुलासा करते हैं कि, अखिलेश और कांग्रेस के बीच अब तक कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई है तथा दोनों के बीच ना तो कोई सीट चिन्हित की गई है और इस संदर्भ में कोई चर्चा भी नहीं हुई है।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस का गठबंधन अभी बरकरार है तथा बिहार में राजद के साथ भी बातचीत चल रही है। तमिलनाडू में द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन जारी है। मूलरूप से यू.पी.ए.-1 का ही गठबंधन जारी है और उसमें उद्धव ठाकरे भी जुड़ गए हैं। उसके अलावा कोई भी नया जुड़ाव नहीं हुआ है।

अब प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि, कमेटी क्या कर रही थी और इसका गठन वास्तव में क्यों हुआ था?

भजन लाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजकोषीय घाटा, 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख रुपए का राजस्व घाटा, दो लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख रुपए राजस्व व्यय, दो लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा चार लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख रुपए का कुल व्यय बताया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस राज में मालपुरा समेत जिन विधानसभा क्षेत्रों को वंचित रखा गया, उन क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय और प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना व क्रमोन्यन के लिए एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

अंतरिम बजट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।

- 33 लाख किसानों को मक्का, बाजरा, सरसों, मूँग ज्वार व मोठ के बीज दिए जाएंगे।
- "प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना" में राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये की।
- "हाइवेज़" पर दुर्घटनाओं में मानव जीवन बचाव के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस।
- प्रत्येक जिले में "एंटी रोमियो स्क्वॉड" का गठन, 174 पुलिस थानों में 'वुमेन हैल्पडेस्क्स' लगेंगी।
- "लाडली सुरक्षा योजना" के तहत सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्राावासों व नारी निकेतनों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण में तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण की घोषणा की गई

■ **राज्यपाल सौंदर्यराजन ने कहा, राज्य सरकार किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, गरीबों, एस.सी. एस.टी. पिछड़े अल्पसंख्यक, सेवानिवृत कर्मचारियों व शहीदों के परिवार के कल्याण व विकास पर कार्य करेगी।**

हैदराबाद, 08 फरवरी। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य में घर-घर जाकर जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधानपरिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, सौंदर्यराजन ने कहा कि, यह सर्वेक्षण सामान्य रूप से विभिन्न जातियों और विशेष रूप से बैकवर्ड कास्ट (बी.सी.) के लिए सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक अवसरों का अनुमान लगाने हेतु आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने वाले समाज के सभी वर्गों को न्याय प्रदान किया जाएगा और सरकार किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, गरीबों, एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शहीदों के परिवारों और अन्य लोगों की कल्याण एवं विकास की आवश्यकताओं पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा, हम जिस तेलंगाना की कल्पना करते हैं, वह एक है, जहां लोकतंत्र फलता-फूलता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की भावना हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है। राज्यपाल ने कहा कि, बजट प्रक्रिया केवल वार्षिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह विकास का एक वाहन है और लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने राज्य में नई सरकार (कांग्रेस) के लिए इतने प्यार से और इतनी भारी संख्या में मतदान किया।

बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, 2024-25 के बजट में, राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधनों का आवंटन कुशलतापूर्वक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि, खर्च किया गया प्रत्येक रुपया तेलंगाना के कल्याण और प्रगति में योगदान देता है।

हल्द्वानी में कर्फ्यू: दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश

■ **अवैध मदरसा और नमाज स्थल हटाने के दौरान भारी पथराव हुआ, जो रात में उग्र प्रदर्शन में बदल गया।**

हल्द्वानी/नैनीताल, 08 फरवरी। उत्तराखंड में हल्द्वानी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के दौरान गुरुवार को हुए भारी बवाल के बाद प्रदेश सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिये हैं। प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

इस घटना की आंच राजधानी देहरादून तक पहुंच गयी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार के साथ उच्चस्तरीय बैठक बुलायी और हालात की समीक्षा की। बैठक में दंगाइयों से सख्ती से निपटने और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिये गये।

धामी ने अधिकारियों को मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश भी दिये। साथ ही लोगों से शांति बनाये रखने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

इसी के मद्देनजर शुक्रवार को हल्द्वानी में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का भी फरमान जारी कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अन्य थानों से भी पुलिस बल एवं पीएसी को बुला लिया गया है।

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और नमाज स्थल हटाने के दौरान आज शाम को भारी बवाल हो गया। एक खास समुदाय के लोगों ने अवैध निर्माण हटाने के दौरान हल्द्वानी नगर निगम की टीम, पुलिस और प्रशासन पर जबर्दस्त पथराव किया और यह क्रम कई घंटों तक चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने अंधेरा होते ही उग्र प्रदर्शन शुरू किया जिससे हालात बेकाबू हो गये। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव करने पर पुलिस, प्रशासन और पत्रकारों के साथ अन्य लोग घायल हो गये।

प्रदर्शनकारियों ने अवैध निर्माण हटा रही निगम की जेसीबी मशीन को तोड़ दिया। बनभूलपुरा थाना के बाहर खड़ी मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। देखते देखते हालात बेकाबू हो गये।

पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ चौथी बार सत्ता में आयेंगे- विदेशी मीडिया

■ **वॉशिंगटन पोस्ट, ब्लूमबर्ग, सी.एन.एन., ए.पी., स्पूतनिक और टेलीग्राफ का आकलन है कि, शरीफ 2024 के आम चुनाव में फिर पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे।**

इस्लामाबाद, 08 फरवरी। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलैट्स और थिंक टैंक्स ने अनुमान जताया है कि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) सुप्रीमो एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2024 के आम चुनाव में चौथी बार देश की बागडोर संभालेंगे।

शरीफ के फिर से पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम बनने का आकलन करने वाले विदेशी मीडिया आउटलैट्स में वाशिंगटन पोस्ट , ब्लूमबर्ग , सीएनएन , एपी , स्पूतनिक और टेलीग्राफ शामिल हैं।

वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि, यह आश्चर्य की बात होगी कि, गुरुवार को जब पाकिस्तानी जनता आम चुनाव में हिस्सा लेगी तो नवाज शरीफ सत्ता में आ सकेंगे। चौथी बार सत्ता में आने के बाद उनके पास उन आरोपों से खुद को मुक्त करने का मौका होगा जिनके कारण उन्हें 2017 में प्रधानमंत्री पद खोना पड़ा था। प्रधानमंत्री होने के नाते नवाज़ शरीफ़ को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के अस्थिर समर्थकों का सामना करना पड़ेगा।

अमेरिकी टेलीविजन ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, पिछले हफ्ते कराची में पाकिस्तान के व्यापारिक अभिजात वर्ग की सभा में शामिल कई लोगों ने त्रिशंकु संसद और फिर कमजोर गठबंधन सरकार की भविष्यवाणी की थी , हालांकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि, इसका नेतृत्व शरीफ़ या उनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ करेंगे।

सीएनएन का कहना है, अनुभवी शरीफ को हालांकि पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो दिवंगत पूर्व नेता बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं।

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस(एपी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, पिछले अक्टूबर में स्वदेश लौटने के बाद अदालतों द्वारा शरीफ की दोषसिद्धि और जेल की सजा को पलटने के बाद उनके पास चौथे कार्यकाल के लिए स्पष्ट रास्ता है।

स्पूतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चुनाव के बाद नये नेता को देश के सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक और बढ़ ती आतंकवाद की समस्या से निपटना होगा।

टेलीग्राफ लिखता है, पूर्व प्रधानमंत्री करीबी लड़ाई के बजाय ताजपोशी की उम्मीद करते दिख रहे हैं क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी इमरान खान आपराधिक दोषसिद्धि के मामलों से जूझ रहे हैं।

अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्ययूट का कहना है, भविष्यवाणी यही है कि नवाज शरीफ और उनके पीएमएलएन के सत्ता जीतने की संभावना है।

एक अन्य अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरैन रिलेशंस ने कहा कि, शरीफ के लिए प्रधानमंत्री बनने और उनकी पार्टी के लिए सशस्त्र बलों के समर्थन के साथ संसद पर नियंत्रण हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

पूर्व वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक और किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर टिम विलासी-विल्सी ने कहा कि शरीफ एक अनुभवी हैं और वह हमेशा अमेरिका तथा चीन के बीच बहुत अच्छा संतुलन बनाने में माहिर रहे हैं। वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908